गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 063
दि. 02.07.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'भारत-पाक के बीच सामान्य हो संबंध', दोनों देशों के 100 से ज्यादा हस्तियों ने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखा पत्र

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के 100 से ज्यादा मशहूर हस्तियों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने को लेकर अपील की है। 30 जून को लिखे गए एक खुले पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ से अपील की है कि वे दोनों पड़ोसी देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करें और सामान्य संबंध बहाल करें। इस ओपन लेटर को 'सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस' के चेयरमैन ओपी शाह ने तैयार किया है।

61 भारतीयों ने किया हस्ताक्षर

61 भारतीयों और 55 पाकिस्तानियों के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में दोनों सरकारों से आग्रह किया गया कि वे 'दक्षिण एशिया में शांति, सामान्य स्थिति, बातचीत और सहयोग बहाल करने की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। साथ ही इस लेटर में इस बात पर जोर दिया गया कि मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखना है।

इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में फ्अह के पूर्व प्रमुख एएस दुलत, राज्यसभा सांसद मनोज झा, हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी के साथ-साथ दोनों देशों के रिटायर्ड राजनयिक और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल हैं।

न्यूज एजेंसी क्अठर से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि इस पहल का मकसद नागरिकों और सरकारों के बीच फर्क को समझते हुए लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। हमारा इरादा हमेशा से एक जैसा रहा है, और मैंने इस बारे में साफ तौर पर लिखा और कहा भी है।

सरकार और नागरिक के बीच फर्क होता है। संगीत के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, फिल्मों के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, और डिजिटल जमाने में कार्टून के लिए भी वीजा की जरूरत नहीं होती। मेरा मतलब है कि संगीत, कविता और कहानियां सरहदों से परे होती हैं।'

झा ने किया पहलगाम हमले का जिक्र

झा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई घटनाओं का भी ज़िक्र किया और बातचीत के कुछ तरीकों के जारी रहने पर सवाल उठाए। हमें अभी भी इस बात से तकलीफ है कि पहलगाम की घटना के बाद दुबई में क्रिकेट खेला गया। क्या पूरा देश दुखी नहीं था? साथ ही, कोलंबो में 'ट्रैक-टू डिप्लोमेसी' (अनौपचारिक बातचीत) चल रही है।'

पत्र लिखने वाले 'प्रो-पाकिस्तान ब्रिगेड' का हिस्साः भाजपा

भारत और पाकिस्तान के

प्रधानमंत्रियों नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ से संवाद बहाल करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की अपील को लेकर दोनों देशों के 100 से अधिक लोगों की ओर से लिखे गए संयुक्त खुले पत्र पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पत्र लिखने वालों की पार्टी प्रवक्ता ने बुधवार को आलोचना की और उन्हें 'प्रो-पाकिस्तान ब्रिगेड' करार दिया। पत्र लिखने वालों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज, एएस दुलत व मणिशंकर अय्यर भी शामिल हैं।

समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रो-पाकिस्तान ब्रिगेड को यह पत्र केवल पाकिस्तान को लिखना चाहिए, क्योंकि भारत का स्पष्ट रुख है कि "बमों और गोलियों की आवाजों' के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के प्रशिक्षण और प्रायोजन को रोकता है, तो ही द्विपक्षीय वाताएं शुरू हो सकती हैं।

'डिजिटल इंडिया' ने भारत को दुनिया में नयी पहचान दिलाईः पीएम मोदी

(जीएनएस)।

नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि इसने शासन के तौर-तरीकों को नया स्वरूप दिया, नागरिकों को सशक्त बनाया और जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सर्वांगीण विकास को गति दी है।

मोदी ने कहा कि 'डिजिटल इंडिया' के 11 वर्ष ने भारत को दुनिया में नयी पहचान दिलाई है।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "आज, डिजिटल इंडिया पहल की शुरूआत के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पहल ने शासन के तौर-तरीकों को नया स्वरूप दिया, नागरिकों को सशक्त बनाया और सर्वांगीण विकास को गति दी है। इसने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लेकर विस्तृत होती डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक, प्रौद्योगिकी लोगों का जीवन आसान बनाने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। उन्होंने कहा, "डिजिटल इंडिया ने नवोन्मेष की लहर को देश के हर हिस्से, विशेषकर गांवों और 'टियर-2' और 'टियर-3' के शहरों तक पहुंचाया है।"

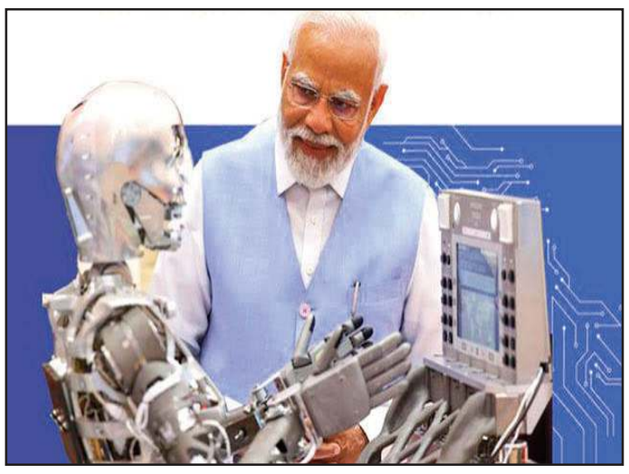

मोदी ने कहा कि देश के हर कोने के युवा उद्यमी, स्टार्टअप और नवोन्मेषक दुनिया के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के समाधान तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वाणिज्य और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत किया है तथा शासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाया है।

मोदी ने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में सरकार की कोशिशों से यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत कृत्रिम मेधा (एआई), सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, "इससे विकास और अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे। हमारा ध्यान ऐसा भविष्य बनाने पर केंद्रित रहेगा जिसमें प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा करे, प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाए और सतत विकास को गति दे।"

मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव है तथा बीते 11 वर्ष में इसने गरीबों और वंचितों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही देशवासियों के जीवन को आसान बनाया है।

उन्होंने कहा, "ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल लेनदेन तक इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता ने दुनियाभर का ध्यान भारत की ओर खींचा है।

मोदी ने कहा, "जब एक अरब से अधिक लोग प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो उसका प्रभाव परिवर्तनकारी होता है।"

जब हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया

राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज 1 जुलाई, 2026 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह न केवल उत्सव मनाने का दिन है, बल्कि इस नए संस्थान की विकास-यात्रा का एक निर्णायक चरण भी है। उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भविष्य के लिए पूर्णतः तैयार संस्थान बनने के लिए यह विश्वविद्यालय एक दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों और विशेषकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, समावेशी और समतामूलक विकास के प्रति उत्तरदायित्व की भावना दशार्ती है।

अखिलेश यादव का जन्मदिन , सीएम योगी और बसपा प्रमुख मायावती समेत कई नेताओं ने दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें सियासी गलियारों से लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने सपा प्रमुख को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीघार्यु की कामना की है।

सीएम योगी ने लिखा, 'उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीघार्यु की प्रार्थना है।'

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीघार्यु की प्रार्थना है।

बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, 'समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें।'

समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और आदि देव महादेव की कृपा अखिलेश यादव पर बरसे और आप सदैव स्वस्थ रहें और दीघार्यु हों।'

'बरेली मंडल में 2155 परियोजनाओं को 15 नवंबर तक करें पूरा', सीएम योगी का अफसरों को कड़ा अल्टीमेटम

(जीएनएस)।

बरेली , सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सर्किट हाउस में मंडलभर के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने की हिदायत दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सर्किट हाउस में बरेली मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान सुस्त अफसरशाही को कड़ा अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री ने दो-टूक निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की 5120 करोड़ रुपये की 2155 विकास परियोजनाओं को आगामी 15 नवंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 15 जुलाई तक हर कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति और 15 अगस्त तक शिलान्यास हो जाना चाहिए, ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके। इन परियोजनाओं में छह बड़े स्टेट हाईवे भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडल में चरमराई बिजली व्यवस्था पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बिजली चोरों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ बड़े अभियान का एलान किया है। सीएम की नाराजगी के बाद जवाब देने के लिए खड़े हुए बिजली निगम के मुख्य अभियंता पूरी बैठक में खड़े ही रहे।

बिजली चोरी रोकने के दिए निर्देश

मंगलवार को सर्किट हाउस में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मंडल में हो रही भारी कटौती के पीछे सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी और ओवरलोडिंग है। इसे रोकने के लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के सघन मोहल्लों में ही अत्यधिक बिजली चोरी की शिकायत होगी। ऐसे इलाकों को सूचीबद्ध करें।

इन इलाकों में बिजली निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर सघन चेकिंग अभियान चलाए और बिजली चोरी करने वालों पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई कर शासन को रिपोर्ट भेजें। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से एक-एक करके कामकाज की जानकारी ली और समस्याओं के बारे में जाना।

समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। कहा कि इससे लोग खासे परेशान हैं। फॉल्ट दूर करने में काफी समय लग रहा है। इस पर सीएम नाराज हो गए। चीफ इंजीनियर से कड़े शब्दों में कहा कि मामला गंभीर है। दो-चार दिन के अंदर सभी कमियों को दूर करें और रिपोर्ट दें। इस पर बरेली के जनप्रतिनिधियों ने बिजली संकट पर बोलना शुरू कर दिया। कहा कि विद्युत निगम के अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते।

निर्माण में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

सीएम ने विधायकों की ओर से दिए गए प्रस्तावों को 15 जुलाई तक बजट के साथ स्वीकृति देने व 15 अगस्त तक उनके भूमि पूजन की तैयारी करने के निर्देश अफसरों को दिए। साथ ही, नवंबर तक इन कार्यों को पूरा कराने की भी हिदायत दी। सड़क, पुल व अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण में शिथिलता बरतने के मामलों में अधिकारियों व संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक, एमएलसी के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

13 जून को महुआ मोइत्रा ने पहले दी चेतावनी अगर अंडे फेंके तो...फिर भी हुई चोर-चोर नारे के हंगामें व 'एग ट्रीटमेंट' की शिकार

पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के एक के बाद एक नेताओं पर अंडे से हमले हुए हैं। इस लिस्ट में पंचायत नेताओं और विधायकों से लेकर सांसद और पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। अब इस लिस्ट में सांसद महुआ मोइत्रा का नाम भी जुड़ गया है।

(जीएनएस)।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने पर 13 जून को चेतावनी देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उन पर अंडे फेंके जाते हैं, तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार से अंडे फेंकने की घटनाओं पर लगाम लगाने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद टीएमसी सांसद अंडे का शिकार

बन गईं। हंगामा करने वालों ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए चोर-चोर की नारेबाजी भी की। महुआ मोइत्रा ने खुद फेसबुक लाइव के जरिए इस घटना के बारे में बताया।

खबर है कि कालीगंज (नादिया जिला) के पलाशीपाड़ा में विधायक अलीफा अहमद के घर पर तृणमूल की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें महुआ शामिल हो रही थीं। उसी समय, प्रदर्शनकारी घर के बाहर जमा हो गए और काले झंडे लहराते हुए वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इसके बाद उन पर अंडे फेंके गए और चोर-चोर के नारे लगाए गए।

महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी सभी इखढ कार्यकर्ता थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और कहा कि देखिए, राज्य में सरकार बदलने के बाद से कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है। पुलिस प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। अब इखढ ने मुझ पर हमले की साजिश रची है। ये आम नागरिक नहीं हैं; ये इखढ कार्यकर्ता हैं। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुँचे, प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें वहां से हटाया।

दुःख बाँटने से कम होता है, आप अकेले नहीं हैं- श्री शिवराज सिंह ने बहनों और जनता से मिलकर सुनी पीड़ा

(जीएनएस)।

अरुणाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार इस संकट में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केयी पान्योर जिले समेत कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही वे सड़क मार्ग से भी गांवों में पहुंचे और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने भावुक अंदाज में कहा कि दुःख बांटने से ही कम होता है और संकट की घड़ी में एक-दूसरे का साथ देना ही जीवन की सार्थकता है। उन्होंने विशेष रूप से बहनों से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि वे अकेली नहीं हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा और जिनके घर बह गए हैं, उनके लिए नए मकान बनवाए जाएंगे। खेतों में हुए नुकसान, फसलों की बबार्दी, पशुधन हानि; सभी का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। तत्काल राहत के रूप में राशन और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं स्थिति को लेकर चिंतित हैं और प्रभावितों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार की टीम राज्य के साथ मिलकर लगातार राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी है।

दौरे के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे सामुदायिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और सुरक्षा दीवार (प्रोटेक्शन वॉल) बनाने के काम में खुद भी हाथ बंटाया और कहा कि समाज की यह भागीदारी प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ से भारी तबाही हुई है और नुकसान का लगातार आकलन किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच सबसे सराहनीय बात यह है कि स्थानीय समुदाय ने सरकार का इंतजार किए बिना खुद आगे बढ़कर समाधान की पहल की है।

सम्पादकीय

धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण - उच्च न्यायालय मद्रास

यह उपाय आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह उपाय आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक लक्ष्यों को कमजोर करता है। अतएव ऐसे उपाय हासिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत हैं।

उच्च न्यायालय मद्रास ने तमिलनाडु सरकार के उस अहम आदेश को रद्द कर दिया,जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े,अति पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी पिछड़े वर्ग मुस्लिमका जाति प्रमाण पत्र ले सकते थे। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण पा लेने की इस सुविधा को न्यायालय ने दो टूक शब्दों में असंवैधानिक माना है। अदालत ने कहा कि धर्म बदलने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिमका दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग-अलग समुदाय और वर्ग होते हैं,परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से? अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है,जबकि हिंदू धर्म में जाती व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच या वर्गभेद है। हमारी राय में कुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। दरअसल इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है, जिसमें सब का दर्जा एक समान रहे। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायामूर्ति जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ले दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेश को आधार बनाया था। जिसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्मांतरित लोगों को तमिलनाडु में अधिसूचित सात पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता था। सरकार ने अपने आदेश में यह प्रविधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,अत्यंत पिछड़ा वर्ग या डी-नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सरकार का तर्क था कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। किंतु अदालत ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। इसी से मिलती-जुलती प्रवृति के एक एक मामले में फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण के लाभ हेतु किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सी सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर के उस फैसले को बरकरार रखा,जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दिया गया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था। लेकिन इस पीठ ने फैसले में साफ किया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और धर्म आधारित आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। यदि धर्म परिवर्तन का मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत इच्छा रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक व्यवहार को क्षति पहुंचेगी। बावजूद सेल्वरानी हिंदू होने का दावा करती है और नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मांगती है,तब यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है। साफ है,वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकती हैं।

संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है,के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

'ब्यूरोक्रेटिक साइलो' खत्म करने के निर्देश, पीएम मोदी का 'गतिशक्ति मास्टर प्लान' क्या है? समझें क्यों जरूरी है

(जीएनएस)।

पीएम मोदी ने केंद्रीय सचिवों के साथ एक लंबी बैठक में सरकारी विभागों के बीच काम के बंटवारे (ब्यूरोक्रेटिक साइलो) को खत्म करने और 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने इस तालमेल को हासिल करने के लिए 'पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की भी बात कही। जान लीजिए ये क्यों है जरूरी।

सचिवों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'सेवा तीर्थ' में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों संग हाईलेवल मीटिंग की। करीब चार घंटे चली इस मैराथन बैठक में सुधार एजेंडे पर व्यापक चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागों के बीच बनी रुकावटों (ब्यूरोक्रेटिक साइलो) को खत्म करें और सरकारी योजनाओं के खास असर पर पूरा ध्यान दें। इस अहम बैठक में भारत के लगभग 80 शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।

सचिवों के साथ पीएम मोदी ने की मैराथन बैठक

सरकार लगातार अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', डिजिटल गवर्नेंस, नियमों में ढील और 'लास्ट-माइल डिलीवरी' जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट सचिव के अलावा बैठक में प्रधानमंत्री के दो प्रधान सचिव, पी.के. मिश्रा और शक्तिकांत दास और सभी प्रमुख विभागों के सचिव भी मौजूद रहे।

अलग-अलग प्रशासनिक सीमाओं से ऊपर उठने के निर्देश

केंद्रीय सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मंत्रालयों को अपनी अलग-अलग प्रशासनिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक एकीकृत और 'पूरे सरकार' वाले नजरिए को अपनाना चाहिए। इस तालमेल को हासिल करने के लिए, उन्होंने 'पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की पुरजोर वकालत की।

गतिशक्ति मास्टर प्लान से बदलेंगे हालात

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूल के तौर पर नहीं, बल्कि डेटा-आधारित और विभागों के बीच तालमेल बिठाने वाले एक जरूरी जरिया के तौर पर पेश किया। जो रुके हुए फैसलों में तेजी ला सकता है। ये अलग-अलग सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सुचारू बना सकता है।

कबाबों और नवाबों का शहर लखनऊ अब नया पार्टी कैपिटल बन गया है

समिट बिल्डिंग ने लखनऊ को नोएडा के बाहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नाइटलाइफ डेस्टिनेशन बना दिया. इसने शहर के पार्टी कल्चर—और उससे जुड़ी समस्याओं—को भी एक ही जगह पर समेट दिया.

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के विभूति खंड में शुक्रवार की रात, पार्टी शुरू होने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है.

कुछ साल पहले, लखनऊ में ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था—एक ऐसा शहर जिसकी पहचान तहजीब, कबाब और पुराने जमाने के आकर्षण से थी, न कि नाइटलाइफ से. फिर भी आज, पुलिस की मौजूदगी उस जगह का हिस्सा बन गई है जो शायद नोएडा के बाहर उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर नाइटलाइफ डेस्टिनेशन बन गया है.

बहुत से लोगों के लिए, लखनऊ में क्लबिंग का मतलब समिट बिल्डिंग है. 17 मंज़िल इस बिल्डिंग का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर 2019 में हुआ था. उद्घाटन से पहले भी वहाँ रेस्टोरेंट चल रहे थे, लेकिन 2019 तक लगभग हर मंज़िल पर एक नाइटक्लब खुल गया था.

आज, समिट के अंदर हर क्लब एक ही तरह के माहौल में चलता है: अंधेरे कमरे, काली दीवारें, नीची छतें और हल्की रोशनी वाले बूथ. लेजर इक्विपमेंट के अलावा कुछ भी चमकदार नहीं होता; ये इक्विपमेंट ज्यादातर खाली फ़्लोर पर इलेक्ट्रिक ब्लू, नियॉन पिंक और हरी रोशनी डालते हैं—यह खालीपन बताता है कि बिल्डिंग अब कैसी हो गई है. लेकिन इन डांस फ़्लोर ने बेहतर दिन भी देखे हैं.

शाम 7 बजे तक, डांस फ़्लोर किसी वेटिंग रूम की तरह दिखते हैं. कुछ लोग जो जल्दी आ जाते हैं, वे अपनी टेबल पर ड्रिंक्स का मजा लेते हैं. कोई नाच नहीं रहा होता, लेकिन ऊ्ख अपना काम शुरू कर चुका होता है. संगीत ठीक सात बजे शुरू हो जाता है, चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं. लाइटें भी उसी समय जल उठती हैं.

बाहर, रात का एक और रूटीन शुरू हो रहा होता है.

रात 11:30 बजे तक, एंट्री गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है. वर्दी पहने पुलिसकर्मी बिल्डिंग के बाहर अपनी जगह ले लेते हैं. प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हर मंज़िल के कॉरिडोर में घूमते रहते हैं. कुछ लोग पार्किंग एरिया के पास रहते हैं और गाड़ियों के आने जाने पर नजर रखते हैं. यह तैनाती अब एक रूटीन बन गई है.

लखनऊ के सबसे व्यस्त नाइटलाइफ हब में वीकेंड की भीड़ को संभालने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समिट बिल्डिंग परिसर

में स्थित विभूति खंड पुलिस चौकी के बाहर पुलिसकर्मी जमा हुए हैं` फोटोः निकिता आरती नवीन/दिप्रिंट

युवा प्रोफेशनल, कॉलेज के छात्र, कपल्स और दोस्तों के ग्रुप अलग अलग मंज़िलों पर घूमते हैं और तय करते हैं कि शाम कहां बितानी है. हर क्लब के दरवाजे पर तैनात बाउंसर अंदर आने वाले संभावित ग्राहकों का स्वागत करते हैं. बॉलीवुड रीमिक्स की आवाज हॉलवे तक आती है. एक मैकडॉनल्ड्स देर रात तक ऑर्डर सर्व करता है. एक 'एनीटाइम फि टनेस' जिम चौबीसों घंटे खुला रहता है. ऑफि स में लाइटें जलती रहती हैं, और किराएदार जरूरत पड़ने पर आम कामकाजी घंटों के बाद भी काम कर सकते हैं. हालांकि, क्लबों को आधी रात तक बंद करना जरूरी होता है. यह पाबंदी सालों की शिकायतों, नगर निगम की छापेमारी, वायरल वीडियो, झगड़ों और निवासियों के बढ़ते दबाव के बाद लगाई गई है. निवासियों का कहना है कि शहर की सबसे मशहूर पार्टी डेस्टिनेशन अब अव्यवस्था का पर्याय बन गई है.

आज 'समिट' एक सफल कहानी भी है और एक सबक भी.

समिट बिल्डिंग ने लखनऊ की नाइटलाइफ को कैसे बदला

द समिट बिल्डिंग ने लखनऊ के बहुत से लोगों को यह सिखाया कि पार्टी में जाना क्या होता है. इसने नाइटलाइफ को लोकतांत्रिक बनाने में मदद की, इसे उन हजारों युवाओं के लिए सुलभ बनाकर जिन्होंने पहले कभी नाइटक्लब में कदम नहीं रखा था. इसने एक टियर-दो शहर के मनोरंजन के साथ संबंध को बदल दिया.

लेकिन इसे कभी भी शहर के नाइटलाइफ के पते के रूप में बनने के लिए नहीं बनाया गया था.

विभूति खंड में स्थित, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, स्कूलों और परिवारों के घरों वाला एक अपस्केल नियोजित इलाका है, यह बिल्डिंग मूल रूप से तेजी से विस्तार कर रहे लखनऊ की आकांक्षाओं को दर्शाती थी.

ऋ्र्ठ रोड और बार्बेक्यू नेशन जैसे रेस्टोरेंट्स परिवारों को वीकेंड लंच के लिए आकर्षित करते थे. ऑफिस जाने वाले लोग काम के बाद यहां रुकते थे. वही बिल्डिंग जो रात में नाइटक्लब की भीड़ से भर जाती थी, दिन में परिवारिक आउटिंग्स की मेजबानी करती थी और को-वर्किंग स्पेसेस की जरूरतें पूरी करती थी.

फिर लखनऊ ने बड़े पैमाने पर पार्टी करना खोज लिया. लखनऊ के विभूति खंड में स्थित समिट बिल्डिंग में रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे और कॉर्पोरेट ऑफि स हैं। पिछले एक दशक में, यह शहर का सबसे मशहूर नाइटलाइफ डेस्टिनेशन बन गया है

जैसे-जैसे मिक्स्ड-यूज कमर्शियल टावर के अंदर फ्लोर दर फ्लोर क्लब्स बढ़ते गए, वैसे-वैसे भीड़ भी बढ़ती गई. शहर का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, छात्र, युवा प्रोफेशनल्स और पड़ोसी जिलों से आने वाले विज़िटर्स सभी समिट तक पहुंचने लगे. वीकेंड पर, एक पूरा नाइटलाइफ इकोसिस्टम एक ही बिल्डिंग के अंदर दिखाई देने लगा.

लेकिन एक ही जगह पर कई क्लब्स का यह केंद्रीकरण, जिसने समिट को सफल बनाया, उसे कमजोर भी बनाता था.

जब किसी एक क्लब के अंदर कुछ गलत होता था, तो वह शायद ही उसी क्लब तक सीमित रहता था. एक फ्लोर पर हुई लड़ाई कुछ ही घंटों में 'समिट' की कहानी बन जाती थी. और क्योंकि यह टावर एक रेजिडेंशियल इलाके के बीच में स्थित था, जो बालकनियों और अपार्टमेंट की खिड़कियों से दिखाई देता था, हर नाइटलाइफ विवाद जल्दी ही रेजिडेंशियल शिकायत बन जाता था.

आधिकारिक शिकायतों या पुलिस रिपोर्टों के सामने आने से बहुत पहले, क्लब्स के अंदर लड़ाइयों और टकरावों के वीडियो हैँ३२अस्र्र ग्रुप्स और सोशल मीडिया फीड्स में घूम रहे थे. धीरे-धीरे, 'समिट' का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग होना बंद हो गया जिसमें रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, एक जिम और एक टूङ्ग्ल्ल'ीं'२ था. यह नाइटलाइफ के लिए—और उससे जुड़ी समस्याओं के लिए एक शॉर्टहैंड बन गया.

नतीजा एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट था जो बहुत अच्छी तरह काम करता रहा, जब तक कि उसने काम करना बंद नहीं कर दिया.

समिट बिल्डिंग की डायरेक्टरी में रेस्टोरेंट, बार, क्लब, ऑफिस और कॉर्पोरेट किराएदारों की लिस्ट है, जो लखनऊ की सबसे व्यस्त मिक्स्ड-यूज जगहों में से एक के तौर पर इसके विकास को दिखाती है` फोटोः निकिता आरती नवीन/दिप्रिंट

'समिट' लखनऊ के लिए पुलिसिंग की सबसे बड़ी चुनौती बना

नाइटलाइफ के मशहूर ठिकाने से पुलिसिंग की चुनौती बनने तक का यह सफर रातोंरात तय नहीं हुआ. यह कई सालों में, एक एक करके हुई घटनाओं के जरिए हुआ.

मई 2021 में, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इमारत के एक क्लब के अंदर महिलाओं का एक ग्रुप एक दूसरे के पीछे भागता, मुक्के मारता और एक दूसरे को जमीन पर पटकता हुआ दिखा; वे अलग होतीं और फिर से एक दूसरे का पीछा करने लगतीं. वीडियो में पुलिस अफसर भी दिखे जो लड़ाई वाली जगह के पास ही खड़े थे. यह फुटेज इतनी तेजी से फैल गई कि एक ही दिन में पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगी.

गलत वजहों से इस इमारत के सुर्खियों में आने का यह आखिरी मामला नहीं था.

2022 तक, दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया कि 'समिट' 'अराजकता का अड्डा' बन गया था, जहाँ बार चलाने वाले खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, नाबालिग शराब पीते हुए देखे जा रहे थे, और महिलाओं के साथ मारपीट और उत्पीड़न के मामले आम हो गए थे.

सितंबर 2025 में, एक ही रात हुई दो अलग अलग घटनाओं के कारण दो पुलिस अफसरों को अपनी पोस्टिंग गंवानी पड़ी. काम से लौट रहे एक नाइटक्लब पीआर मैनेजर को गोली मारे जाने और एक मारपीट की घटना (जिसका वीडियो वायरल हुआ था) के बाद विभूति खंड के एसएचओ और समिट बिल्डिंग आउटपोस्ट के इंचार्ज को हटा दिया गया.

इससे तीन दिन पहले ही, इलाके की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इन दोनों घटनाओं से परे कई शिकायतें दर्ज कराई थीं: शोर शराबा, पार्किंग में जाम और इलाके की कार पार्किंग से बाहर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या.

कुछ दिनों बाद, लखनऊ पुलिस और आबकारी विभाग ने इलाके में संयुक्त निगरानी शुरू की और वीकेंड की रातों में 11:30 बजे के बाद इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया. दिसंबर तक, नगर निगम ने 'समिट' पर छापा मारा और कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इमारत के कुछ हिस्सों को सील कर दिया.

तब से, पुलिसकर्मी रात करीब 2 बजे तक 'समिट' के अंदर तैनात रहते हैं, और अब इमारत के अंदर ही एक स्थायी पुलिस आउटपोस्ट काम करता है.

लेकिन अपराध और विवाद कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए.

ऋ्र्ठ रोड और बार्बेक्यू नेशन जैसे रेस्टोरेंट वीकेंड पर लंच के लिए परिवारों को आकर्षित करते थे. ऑफिस जाने वाले लोग काम के बाद यहाँ रुकते थे. वही बिल्डिंग, जो रात में नाइटक्लब की भीड़ से भर जाती थी, दिन में परिवारों के घूमने फिरने और को वर्किंग स्पेस के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी.

फिर लखनऊ को बड़े पैमाने पर पार्टी करने का चस्का लगा.

इस साल जनवरी में, एक बिजनेसमैन को एक रवश ने टक्कर मार दी और वह लगभग 25 मिनट तक बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी के पहियों के नीचे फंसा रहा. उसने तब बीच बचाव करने की कोशिश की थी जब उत्तराखंड के कुछ युवाओं का एक ग्रुप, जो रवश में था, दूसरी कार में सवार लोगों से झगड़ रहा था. लेकिन आरोप है कि उस ग्रुप ने उसे गाड़ी से कुचल दिया और उसे गाड़ी के नीचे फंसा हुआ छोड़ दिया.

इस साल 26 मई को, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 28 साल के एक नेता के साथ एक नाइटक्लब के बाहर मारपीट हुई; यह झगड़ा कथित तौर पर सिगरेट को लेकर शुरू हुआ था. तीन दिन बाद, चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. अगले वीकेंड तक, इलाके के अउढ और रलड का फिर से ट्रांसफर कर दिया गया.

इन बार बार होने वाली घटनाओं ने एक बड़ी समस्या को उजागर किया. समिट की मुश्किलें कभी भी सिर्फ अलग अलग क्लबों तक सीमित नहीं थीं; इनकी जड़ शहर की ज्यादातर नाइटलाइफ को एक ही बिल्डिंग में समेटने में थी.

एक ही बिल्डिंग में दर्जन भर नाइटक्लब, रेस्टोरेंट और ऑफि स स्पेस बना दिए जाएं. लखनऊ और आसपास के ज़िलों से लोगों को एक ही पते पर बुलाया जाए. हर रात लगभग एक ही समय पर सैकड़ों लोग सड़कों, सीढ़ियों, लिफ़्ट और पार्किंग लॉट में उमड़ पड़ते हैं. तब वह बिल्डिंग नाइटलाइफ डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेशर सिस्टम की तरह काम करने लगती है. किसी एक जगह पर हुआ मामूली झगड़ा भी तेजी से कॉरिडोर तक फैल सकता है.

यह कहानी है कि कैसे लखनऊ ने रातोंरात पार्टी कल्चर बनाया, कैसे वह कल्चर उस बिल्डिंग से बड़ा हो गया जिसमें वह फला फूला, और कैसे पार्टी पसंद करने वाला एक टियर 2 शहर अभी भी इसे सही ढंग से करना सीख रहा है.

समिट से पहलेः लखनऊ का पुराना क्लब कल्चर लखनऊ के बाहर आम धारणा यह है कि नाइटलाइफ यहां हाल ही में आई है.

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कहते हैं कि यह बात सिर्फ. आंशिक रूप से सच है. समिट के बनने से बहुत पहले ही शहर में पार्टी कल्चर मौजूद था.

वहां होटल क्लब, सिर्फ.मेंबर्स के लिए बनी जगहें और अलग-अलग इलाकों में फैली नाइटलाइफ की जगहें थीं. भीड़ कम होती थी, ज्यादा एक्सक्लूसिव होती थी और अक्सर लोग एक-दूसरे को जानते थे.

'माई बार हेडक्वार्टर्स' के रेस्टोरेंट मैनेजर वासी हैदर ने कहा, 'मैं 18 साल से क्लबिंग सीन से जुड़ा हूं. उस समय जीरो डिग्री और ब्लू जैसे क्लब मशहूर थे. वहीं से इसकी शुरूआत हुई थी.'

पुराने क्लब भी अलग तरह के होते थे. उन्होंने कहा, 'ज्यादातर क्लबों का अंदर का माहौल अंधेरा होता था, एक बड़ा हॉल होता था, सोफे लगे होते थे और जोरदार म्यूज़िक बजता था. आज के क्लबों का डिजाइन अलग है, साउंड सिस्टम बेहतर हैं, खुली छतें हैं और माहौल भी बिल्कुल अलग है.'

2000 के दशक के ज्यादातर समय और 2010 के शुरूआती सालों में, क्लब जाना मुख्य रूप से अमीर लोगों की ही गतिविधि थी.

हैदर ने कहा, 'उस समय, अपर-मिडल क्लास के लोग भी क्लब आने से डरते थे. उन्हें पता नहीं होता था कि उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं.'

वहीं दूसरी ओर, जेनेसिस और चांसलर्स क्लब जैसे क्लबों में परिवार इकट्ठा होते थे. बच्चे खेलते थे और बड़े लोग आपस में घुलते-मिलते थे. म्यूज़िकल शामें, कम्युनिटी इवेंट और वीकेंड पर लोगों का मिलना-जुलना आम बात थी.

मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई में काम करने के बाद शहर लौटीं एक महिला को वे दिन बहुत अच्छे से याद हैं. उन्होंने कहा, 'वहां हमेशा कोई न कोई अच्छा म्यूज़िकल इवेंट होता रहता था. तीन-चार जोड़ों का ग्रुप इकट्ठा होता था और बच्चे एक कोने में खेलते थे. यह एक अच्छा और सुखद अनुभव होता था.'

उन्हें आज की नाइटलाइफ अलग लगती है. 'मजे करने का तरीका बदल गया है. अब यह ज्यादातर EDM म्यूज़िक, देर रात तक जागने और शराब पीने के बारे में है.

द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के इंतजाम की तैयारी

कैबिनेट ने एनएच (ओ) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर 6969.67 करोड़ रुपये की लागत से 8.1 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 6 लेन की सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी, यह सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने आज एनएच (ओ) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएम) पर द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, दिल्ली से जोड़ने वाले एनएच-148एई के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर और कुल पूंजी लागत 6969.67 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगी, जिससे यूईआर 2/द्वारका एक्सप्रेसवे दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज से जुड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम, द्वारका, आईजीआई हवाई अड्डे और पश्चिम दिल्ली से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को भी लाभ मिलेगा। भूमिगत दोहरी सुरंग से सतह पर यातायात व्यवधान कम से कम होगा और दक्षिणी रिज वन (सुरंग का 1.98 किमी भाग रिज के नीचे से गुजरता है) संरक्षित रहेगा। एनएचएआई एम्स और महिपालपुर के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव कर रहा है। यह लिंक सुरंग को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा, जिससे पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से जुड़ जाएंगे।

प्रस्तावित सुरंग रंगपुरी (दक्षिणी दिल्ली) रिज से होकर गुजरती है, जिसे एक ट्विन-ट्यूब सुरंग (टीबीएम के माध्यम से निर्मित की जाएगी) के रूप में डिजाइन किया गया है, यह शिवमूर्ति इंटरचेंज से शुरू होती है और नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर छतरपुर रोड के चौराहे से पहले समाप्त होती है।

इस चौराहे पर भीड़भाड़ कम करने के लिए नेल्सन मंडेला मार्ग के समानांतर एक एलिवेटेड रोड (1.8 किमी) प्रस्तावित है। छतरपुर से महिपालपुर की ओर वर्तमान फ्लाईओवर के समानांतर एक अतिरिक्त फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है। छतरपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए दाएं मुड़ने की सुविधा हेतु एक एलिवेटेड यू-टर्न भी प्रस्तावित है।

मुख्य कैरिजवे की लंबाई 6.3 किमी है। महिपालपुर छतरपुर रोड पर प्रस्तावित फ्लाईओवर और एलिवेटेड यू टर्न को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की कुल लंबाई 8.100 किमी है, जिसमें 3.140 किमी सुरंग, 0.980 किमी सुरंग अप्रोच रैंप, 0.554 किमी आरई वॉल के साथ अप्रोच, 2.556 किमी एलिवेटेड भाग और 0.870 किमी एट-ग्रेड सड़क शामिल है।

अनुमान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक लेन-किलोमीटर के विकास से औसतन 264 व्यक्ति-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और औसतन 55 व्यक्ति-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने दक्षिण पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला

(जीएनएस)।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, एवीएसएम, एसएम ने दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है।

जून 1989 में 47 बख्तरबंद रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल ऑफिसर के पास 37 वर्षों से अधिक का विशिष्ट सेवा का अनुभव है, जिसमें कमान, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी सभी महत्वपूर्ण स्तरों पर कार्य शामिल हैं। कार्यभार संभालने से ठीक पहले उन्होंने पूर्वी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने संचालन संबंधी तत्परता, संगठनात्मक प्रभावशीलता और संस्थागत सामंजस्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उनके कमान अनुभव में सेना के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण परिचालन शामिल हैं, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर, बख्तरबंद रेजिमेंट, स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड, बख्तरबंद डिवीजन और रेगिस्तान कोर शामिल हैं। इन नियुक्तियों ने उन्हें विभिन्न मोर्चों पर जटिल बहु-क्षेत्रीय अभियानों की संचालन योजना और संचालन में व्यापक विशेषज्ञता प्रदान की है। उनके पास कमान के अलावा संचालन योजना, सैन्य खुफिया, संचालन रसद, कार्मिक प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने और रणनीतिक संवाद सहित प्रमुख स्टाफ पदों पर कार्य करने का व्यापक सैन्य अनुभव है।

लेफ्टिनेंट जनरल मल्होत्रा एक उच्च कोटि के विद्वान-सैनिक हैं। उनके पास रक्षा अध्ययन में दो स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं, जिनमें एक किंग्स कॉलेज, लंदन की डिग्री शामिल है। इसके अलावा, उनके पास राजनीति विज्ञान और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में दो एमफिल डिग्रियां भी हैं। उन्होंने अपने सभी पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जनरल ऑफिसर यूनाइटेड किंगडम के एडवांस्ड कमांड एंड स्टाफ कोर्स, हायर एयर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक से सम्मानित किया गया है। उन्‍ हें सेना कमांडरों और सेना प्रमुख से कई प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा के नाम उत्कृष्ट संचालन क्षमता, रणनीतिक स्पष्टता और संस्थागत नेतृत्व का एक स्थापित रिकॉर्ड है। रणनीतिक रूप से सबसे अधिक महत्‍ वपूर्ण कमानों में से एक का इनका नेतृत्‍ व भारतीय सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध बनाता है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

आखिर 1600 सीसीटीवी कैमरों की नजर से कैसे बच गई अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी?

राम मंदिर में सुरक्षा और निगरानी के लिए कम से कम 1600 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण के बाहर भी हजारों कैमरे लगे हैं। लेकिन 'जब ऊपर वाला सब देख रहा था', फिर भी करोड़ों रुपए कैसे चोरी हो गए? यह अभी तक रहस्य ही है।

(जीएनएस)।

अयोध्या राम मंदिर में 'चंदा चोरी' का रहस्य सुलझने के बजाए गहराता जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) बना, एफआईआर हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और राम मंदिर ट्रस्ट के कुछेक पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित हैं, जिन पर न तो ट्रस्ट, न संघ, न बीजेपी और न ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ बोल रही है।

सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी की चुनावी राजनीति का मुख्य मुद्दा बना अयोध्या में राम मंदिर क्या इतनी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था से प्रबंधित हो रहा था या है कि वहां से करोड़ो रुपए (पूरा आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है) का चंदा चोरी हो गया। देश के करोड़ों नागरिकों की तमाम तरीकों से निगरानी करने वाली सरकार क्या चंदे की निगरानी की व्यवस्था करने में नाकाम रही। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर प्रांगण में जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनमें पल-पल की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग होती है। राजनीति

अयोध्या राम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से करीब 800 से 1,600 कैमरे सीधे मंदिर परिसर, दान पेटी और गर्भगृह की निगरानी के लिए हैं। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए इनमें से कई कैमरों में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंदिर परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए आधुनिक कैमरे 24७7 सक्रिय रहते हैं।

इन सभी कैमरों की लाइव फीड पुलिस और सुरक्षा बलों के विशेष कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड की जाती है।

अऋएफळकरएटएठळ

मंदिर में दान-पात्रों और चढ़ावे की गिनती वाले कमरों में विशेष हाई-डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

यह तो रही जानकारी पूरे मंदिर परिसर में लगे कैमरों की। लेकिन फोकस में दान पात्र और वह कक्ष है जहां चढ़ावे में आए चंदे की गिनती आदि होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मंदिर परिसर में अलग-अलग जगहों पर 40 दान पात्र रखे गए हैं। इन्हीं दान पात्रों में श्रद्धालु अपनी हैसियत मुताबिक नकद रकम, नोट, सिक्के, सोने-चांदी के गहने आदि डालते हैं। इन दानपात्रों को मंदिर उद्घाटन के शुरूआती दिनों में दिन कम से कम दो बार खोला जाता था क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आ रहे थे और दान पात्रों में चंदा डाल रहे थे। फिलहाल कितनी बार दानपात्रों को खोला जाता है इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं है।

दानपात्र खोलने की एक प्रक्रिया तय की गई थी। इसके तहत दान पात्र खोलते समय मंदिर ट्रस्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी, इस काम के लिए विशेष रुप से नियुक्त कर्मचारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी या कर्मचारी की मौजूदगी में खोला जाता है। इन पात्रों में मिले पैसे-गहनों आदि को लोहे को कंटेनर में तालाबंद कर गणना कक्ष में ले जाया जाता है।

दान गणना कक्ष (काउंटिंग रूम) मंदिर परिसर के अंदर, मुख्य मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में स्थित है।यह स्थल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा घेरे के अंतर्गत आता है।

गणना कक्ष में सभी 40 दानपात्रों से मिला धन लाया जाता है। इस गणना कक्ष में 44 लोगों की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। इनमें एक इंचार्ज होता है, एक सुपरवाइजर और 4-5 टेलर यानी रोकड़िया है जो पैसे का लेन-देन करता है। इस टीम में ट्रस्ट के अधिकारी, बैंक के अधिकारी कुछ स्थानीय वॉलंटियर होते हैं जिन्हें ट्रस्ट ने नियुक्त किया होता है। गिनती करने वाले लोगों के लिए बिना जेब के कपड़े पहनने का नियम बनाया गया था जिसपर स्टेट बैंक और ट्रस्ट दोनों सहमत हुए थे। लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।

दानपात्रों की लोकेशन, उससे मिले धन को गणना केंद्र तक लाने वाले रास्ते और गणना कक्ष, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। रिपोर्ट में सामने आया है कि सभी कैमरों की स्टोरेज क्षमता सिर्फ 45 दिन की रिकॉर्डिंग रखने की ही है और उसके बाद सारी फुटेज वह ऑटो डिलीट हो जाती है। यह ऐसा पेंच है जिसका जवाब फिलहाल नहीं मिला है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एसआईटी डिलीट हुए फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है।

गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी की जो भी रिकॉर्डिंग मिली है, उसमें कुछ चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं। रिकॉर्डिंग से पता चला है कि गिनती के दौरान नोटों के बंडल तय की गई ट्रे या बैंक के कंटेनर में न रखकर कुछ खास व्यक्तियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। यह खास व्यक्ति कौन हैं, इसका खुलासा होना बाकी है।

एक और अहम खामी गणना कक्ष में सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गिनती में लगे कुछ कर्मचारी खासतौर से गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन के सामने इस तरह बैठते हैं जिससे पूरे कमरे और पूरी प्रक्रिया सामने आ ही नहीं पाती है। यानी कैमरे के लेंस में उनकी पीठ ही नजर आ पाती है।

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मंदिर परिसर में लगे हर कैमरे की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। तो फिर कैमरों के सामने आ रहे ऐसे व्यवधान को नोट क्यों नहीं किया गया और इसकी जानकारी ट्रस्ट को कैसे नहीं हुई?

अऋएफळकरएटएठळ

यहां एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। अर्जुन देव...यह सरकारी कर्मचारी हैं और अयोध्या में बीते 17 साल से रेडियो मेंटेनेंस अधिकारी के तौर पर तैनात थे। मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करना इनकी ही जिम्मेदारी थी। लोगों का कहना है कि यह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (जो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफे की मंजूरी अभी बाकी है) के नजदीकी थे। एसआईटी की जांच के दौरान इनका नाम सामने आया है। लेकिन इससे पहले ही इनका तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इनसे पूछताछ नहीं हुई है। कहा जाता है कि पूर्व में भी इनके तबादले के आदेश होते रहे लेकिन हर बार किसी न किसी की सिफारिश से इनका तबादला रोक दिया गया था।

इन सारी बातों और जानकारियों के सामने आने के बाद अब साफ होता जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी महज एक खानापूरी थी, और उनकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूरे परिसर में ऐसे कई ब्लाइंड स्पॉट भी मौजूद हैं जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर नहीं पहुंच पाती।

चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने सीए को बधाई दी

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने सीए को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर सीए को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बधाई देते हुए लिखा, 'पूरे सीए समुदाय को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' की बधाई। वे लंबे समय से भारत की आर्थिक यात्रा में भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से, वे हमारे वित्तीय सिस्टम को मजबूत करते हैं, व्यवसायों को सहारा देते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं।'

प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर आगे लिखा, 'उनकी विशेषज्ञता आर्थिक विकास और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे हम 'विकसित भारत' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कोशिशें ऐसा माहौल बनाने में मदद करती हैं जहां उद्यम फल-फूल सकें और सभी के लिए अवसर बढ़ सकें।'

गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। वे व्यक्तियों और व्यावसायिक घरानों की वित्तीय दक्षता और कानूनी अनुपालन को लगातार बेहतर बनाकर हमारे देश की आर्थिक प्रगति में

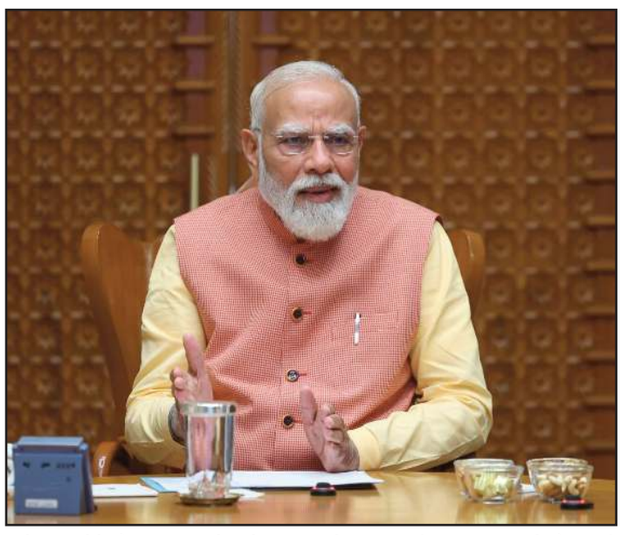

योगदान देते हैं। यह दिन देश के प्रति उनके समर्पण को और मजबूत करे।'

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'वित्तीय ईमानदारी और आर्थिक प्रगति के आधार-स्तंभों को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' की हार्दिक शुभकामनाएं। नैतिकता, सटीकता और पारदर्शिता के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से, आप व्यवसायों को मजबूत बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने और भारत की प्रगति व समृद्धि में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी सीए पेशेवरों को उनके इस नेक पेशे में निरंतर सफलता और उत्कृष्टता की शुभकामनाएं।'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट साथियों को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी विशेषज्ञता, निष्ठा और व्यावसायिक उत्कृष्टता देश की आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में आपका योगदान अत्यंत अभिनंदनीय है।'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी विशेषज्ञता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव है।'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय को बधाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत की विकास यात्रा में भरोसेमंद साझेदार हैं। स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने और एमएसएमई को मजबूत करने से लेकर पारदर्शिता, नियमों के पालन और वित्तीय अनुशासन के साथ उद्यमों को सहयोग देने तक, आपका योगदान एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर रहा है। देश के प्रति समर्पित सेवा के लिए हर सीए को शुभकामनाएं।

लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के सात अंडरग्राउंड स्टेशनों का निर्माण शीघ्र, सबसे बड़ा सिविल टेंडर जारी

लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पूरा होने पर चारबाग से वसंतकुंज तक तेज, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। ..

चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित 11.165 किलोमीटर लंबा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर ₹1877.89 करोड़ की अनुमानित लागत से चारबाग से चौक तक बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो सेक्शन

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-1बी) के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित 11.165 किलोमीटर लंबे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत बनने वाले 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों एवं संबंधित सुरंग निर्माण के लिए लगभग ₹1877.89 करोड़ का प्रमुख सिविल निर्माण टेंडर जारी कर दिया गया है। यह परियोजना लखनऊ मेट्रो फेज-1बी का अब तक का सबसे बड़ा सिविल टेंडर है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि यूपीएमआरसी लगभग ₹5801 करोड़ की लागत से लखनऊ मेट्रो फेज-1बी (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) का निर्माण कर रहा है। परियोजना के तहत पांच

एलिवेटेड एवं सात अंडरग्राउंड सहित कुल 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। एलिवेटेड व अंडरग्राउंड दोनों सेक्शन का निर्माण समानांतर रूप से किया जाएगा, जिससे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो संचालन शुरू किया जा सके।

28 जुलाई को खोला जाएगा टेंडर

टेंडर प्रक्रिया के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को टेंडर खोला जाएगा। सफल बोलीदाता के चयन के बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा तथा कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 36 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इस टेंडर के अंतर्गत चारबाग से चौक तक अंडरग्राउंड मेट्रो सेक्शन का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक सुरंग निर्माण के साथ सात अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का निर्माण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, चौक मेट्रो स्टेशन से एलिवेटेड कॉरिडोर को जोड़ने के लिए लगभग 350 मीटर लंबा रैंप भी निर्मित किया जाएगा।

यूपीएमआरसी ने ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन के लिए पांच मेट्रो स्टेशनों, वायाडक्ट तथा वसंतकुंज मेट्रो डिपो के निर्माण से संबंधित टेंडर पहले ही जारी कर दिया है। अब अंडरग्राउंड सेक्शन का टेंडर जारी होने के साथ परियोजना के सभी प्रमुख सिविल पैकेजों की निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-1बी) में सात अंडरग्राउंड स्टेशन

चारबाग मेट्रो स्टेशन, गौतमबुद्ध मार्ग मेट्रो स्टेशन, अमीनाबाद मेट्रो स्टेशन, पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन, सिटी मेट्रो स्टेशन, मेडिकल चौराहा मेट्रो स्टेशन, चौक मेट्रो स्टेशन

परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने में मदद

एमडी, यूपीएमआरसी सुशील कुमार ने बताया कि अंडरग्राउंड सेक्शन के इस प्रमुख सिविल टेंडर का जारी होना लखनऊ मेट्रो फेज-1बी परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एलिवेटेड एवं अंडरग्राउंड दोनों सेक्शन पर समानांतर कार्य शुरू होने से परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पूरा होने पर चारबाग से वसंतकुंज तक तेज, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इससे पुराने लखनऊ सहित घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, सड़क यातायात का दबाव कम होगा तथा शहर में टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: एसआईटी को मिला 15 दिन का और वक्त, अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा

एसआईटी अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

(जीएनएस)।

लखनऊः अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से सात करोड़ रुपये के चढ़ावे की चोरी के मामले में गठित विशेष जांच दल (रक्ळ) को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रक्ळ के कार्यकाल को बढ़ाया गया है. अब जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, यह मामला बीते जून में तब सुर्खियों में आया था जब विपक्षी दलों ने दानपात्र से चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाया था. उसके बाद 13 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की रक्ळ से जांच कराने का अनुरोध किया था. सरकार ने तत्काल तीन सदस्यीय रक्ळ का गठन किया, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त कअर विजय विश्वास पंत, आईजी रेज क्ढर किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.

शुरूआत में रक्ळ को 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसमें सात दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी. अब समय सीमा बढ़ने के बाद टीम मंदिर प्रशासन, चढ़ावा गिनने वाले करीब 50 कर्मचारियों और पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी. रक्ळ अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़; फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जांच के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी.

(जीएनएस)।

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है. लखनऊ कमिश्नरेट की साइबर सेल और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने गोमतीनगर स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा. पुलिस ने 119 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल, कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कॉल सेंटर के जरिए विदेशों के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की जा रही थी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी. साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस गिरोह को आर्थिक लाभ किसे मिल रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन में की गई. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार और पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव की निगरानी में साइबर सेल और साइबर थाना की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद कार्रवाई की गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर दो अलग-अलग कार्यालयों से यह फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था.

पुलिस की जांच में पता चला है कि यहां काम करने वाले लोग मुख्य रूप से रात के समय विदेशी नागरिकों को फोन करते थे. उन्हें तकनीकी समस्या, निवेश, डॉलर ऐप और अन्य तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते थे. जिसके बाद अलग-अलग तरीकों से उनसे पैसे ठगे जाते थे. पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार देश के बाहर तक जुड़े हो सकते हैं.

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मूलरूप से अहमदाबाद (गुजरात) के रहने वाले ललित खैराजानी और वर्तमान में गोमती नगर विस्तार में रह रहे विक्रम सिंह परमार को भी हिरासत में लिया है. दोनों आरोपी वर्तमान में गोमती नगर में रह रहे थे. दोनों कॉल सेंटर में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

रामराज्य कोष लिखा संदूक का बरामद होना साजिश का संकेत

(जीएनएस)।

राम मंदिर गबन मामला एक संगठित अपराध जैसा सामने आ रहा है। आरोपी अविनाश शुक्ला जिस योग केंद्र में नौकरी करता था, वहां से बरामद रामराज्य कोष लिखा संदूक का बरामद होना यही बता रहा है।

अयोध्या के राम मंदिर चोरी मामले में शक की सुई आरोपी अविनाश शुक्ला पर जाकर ठहर गई है। मामले के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला (जो जेल में बंद है) के ठिकानों पर पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने उस योग केंद्र पर छापेमारी की जहां अविनाश शुक्ला रहता था। तलाशी के दौरान पुलिस ने योग केंद्र से एक संदूक बरामद किया है, जिस पर "रामराज्य कोष" लिखा हुआ है। इसमें कितनी नकदी मिली है, पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। इस संदूक पर एक क्यू आर कोड भी छपा हुआ मिला है। पुलिस अब इस दफकोड से जुड़े बैंक खातों और इसके जरिए हुए सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री खंगाल रही है, ताकि अवैध रूप से जुटाए गए चंदे के मुख्य स्रोत का पता लगाया जा सके। पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है, जिसके कहने पर रामराज्य कोष बनाया गया।

अविनाश शुक्ला के इतिहास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जो इस पूरी साजिश की गहराई को दर्शाती हैंः अविनाश मूल रूप से किसी दूसरे जिले का रहने वाला है। करीब डेढ़ साल पहले वह इस क्षेत्र में आया और इस योग केंद्र में पनाह ली। योग केंद्र में रहने के दौरान ही उसने योजनाबद्ध तरीके से राम मंदिर में नौकरी हासिल की। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि एक बाहरी व्यक्ति को इतनी आसानी से मंदिर परिसर और चंदा प्रबंधन से जुड़ी नौकरी दिलाने में किन लोगों ने पैरवी की थी।

शुक्ला उन आरोपियों में शामिल है जिसे राम मंदिर में कैश गिनने के काम पर लगाया गया था। एसबीआई ने जब अविनाश शुक्ला समेत सभी 8 लोगों को हटाना चाहा तो राम मंदिर ट्रस्ट ने इन 8 लोगों को नहीं हटाने के लिए दबाव बनाया। अविनाश शुक्ला ही वो आरोपी है जिसके घर से 80 लाख रुपये बरामद किए गए।

मामले की गंभीरता और इसमें शामिल बड़े नेटवर्क को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (रक्ळ) को और समय दे दिया है। रक्ळ को अब अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई अवधि में रक्ळ वित्तीय हेरफेर और डिजिटल फॉरेंसिक साक्ष्यों को और मजबूत करेगी।

अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, दान की निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए उन सभी लोगों को जांच के दायरे में लाया गया है जिनकी जिम्मेदारी दान के पैसों की गिनती करने, उसे बैंक में जमा करने या सुरक्षा व्यवस्था को देखने की थी। पुलिस यह पता लगा रही है कि इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी हेराफेरी बिना किसी आंतरिक मिलीभगत या बड़ी लापरवाही के कैसे चलती रही।

यूपी में जमीन के विवादों का होगा डिजिटल समाधान, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा खास पैमाइश अभियान

अत्याधुनिक तकनीक से भूमि संबंधी लंबित विवादों का होगा समाधान।

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सहारनपुर में प्रदेशव्यापी "डिजी रोवर (डिजी रोवर-जीएनएसएस) विशेष भूमि पैमाइश अभियान" का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डिजी रोवर (जीएनएसएस) तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित समाधान और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सटीक एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

डिजी रोवर तकनीक से सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवादों को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजी रोवर (जीएनएसएस) तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं

उपलब्ध हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है और इससे राजस्व प्रशासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। राज्य सरकार किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भूमि संबंधी विवाद ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बड़ी चुनौती रहे हैं। डिजी रोवर अभियान के माध्यम से इन विवादों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य केवल लंबित मामलों का निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित कर भूमि संबंधी विवादों को न्यूनतम स्तर तक लाना है।

पैमाइश की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी मानकों के अनुरूप हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और मिशन मोड में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अभियान का लाभ निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। साथ ही अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पैमाइश की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी मानकों के अनुरूप हो और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान समय में धारा-24 के तहत भूमि पैमाइश एवं सीमांकन से संबंधित करीब 79,157 प्रकरण लंबित हैं।

योगी सरकार का अभियान के माध्यम से इन मामलों का मिशन मोड में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने का लक्ष्य है, जिससे किसानों एवं आम नागरिकों को वर्षों से लंबित समस्याओं से राहत मिल सके। सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व परिषद द्वारा सभी जनपदों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। अभियान का समग्र पर्यवेक्षण एवं उच्च स्तरीय अनुश्रवण राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल द्वारा किया जाएगा, जबकि अभियान की नियमित समीक्षा, प्रगति की मॉनिटरिंग तथा आवश्यक दिशा-निर्देश आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा दिए जाएंगे।

तय समयावधि के भीतर अधिकतम लंबित पैमाइश प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के सफल संचालन में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (राजस्व), उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल समन्वित रूप से कार्य करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के भीतर अधिकतम लंबित पैमाइश प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य दिया गया है। यह अभियान न केवल लंबित पैमाइश मामलों के त्वरित निस्तारण में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भूमि संबंधी विवादों में कमी लाने, किसानों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तकनीक आधारित सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'डॉक्टर्स डे' पर पीएम मोदी ने वेनेजुएला में सेवाएं दे रहे भारतीय चिकित्सकों को किया नमन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (डॉक्टर्स डे) के अवसर पर वेनेजुएला में सेवा दे रहे भारतीय डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे भारतीय चिकित्सा पेशेवर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (डॉक्टर्स डे) के अवसर पर वेनेजुएला में सेवा दे रहे भारतीय डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे भारतीय चिकित्सा पेशेवर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा, "आज, जब हम डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, मैं 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत वेनेजुएला में अथक सेवा दे रहे भारत के सभी डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सराहना करता हूं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनके प्रयास इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि जब भी समाज किसी चुनौती का सामना करता है, हमारे चिकित्सा पेशेवर हमेशा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय

डॉक्टरों की प्रतिबद्धता, सेवा भावना और मानवीय दृष्टिकोण पूरी दुनिया में भारत की सकारात्मक पहचान को मजबूत कर रहा है। उन्होंने चिकित्सा समुदाय के योगदान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

इससे पहले की एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण, करुणा और अथक सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मेहनत, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता ही भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "डॉक्टर्स डे पर हमारे समर्पित चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी कड़ी मेहनत, करुणा और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उनके अथक प्रयासों ने करोड़ों लोगों का विश्वास और आभार अर्जित किया है।"

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है, जबकि स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है।

पीएम मोदी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह अभूतपूर्व विस्तार भावी डॉक्टरों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है, देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मजबूत मानव संसाधन तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं देश के हर कोने तक पहुंचें।

उन्होंने कहा, " विकसित भारत के निर्माण की दिशा में डॉक्टरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर न केवल निवारक स्वास्थ्य सेवाओं (प्रिवेंटिव हेल्थकेयर) को बढ़ावा देंगे, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने, नवाचार को अपनाने तथा सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।" प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और चिकित्सा समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका योगदान स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अमूल्य है।

'ऑपरेशन अमिस्ताद' भारत सरकार की ओर से वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद शुरू की गई मानवीय पहल है। एचएडीआर मिशन के तहत भारत ने 41 सदस्यीय चिकित्सा दल, दो 'भीष्म' पोर्टेबल अस्पताल और 66 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री और दवाइयां वेनेजुएला भेजी हैं।

गुरुवार से शुरू होगी यूपी टीईटी परीक्षा, लखनऊ क्षेत्र में चलेंगी 1000 रोडवेज बसें; कर्मचारियों की छुट्टियां रद

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) गुरुवार से शुरू हो रही है। राजधानी में 96 हजार से अधिक परीक्षार्थी तीन दिन की परीक्षा में विभिन्न पालियों में शामिल होंगे। सभी परीक्षार्थी गैर जिलों से राजधानी आएंगे, जबकि राजधानी के परीक्षार्थियों को दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है।

परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 1000 बसों का संचालन कर रहा है। अनुबंधित बसों को भी पूरी क्षमता के साथ सड़क पर उतारने के कड़े निर्देश हैं। निगम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 8726005808 है।

लखनऊ में परीक्षा के लिए कुल 46 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दो और तीन जुलाई को परीक्षा दो पालियों में और चार जुलाई को प्रथम पाली में होगी। हर केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू

होने से 45 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली अपराह्न 2:30 बजे से पांच बजे तक होगी।

स्टाफ की तीन दिनों तक 24 घंटे रहने के लिए ड्यूटी लगाई गई

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया, लखनऊ क्षेत्र की सभी 1000 बसों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों के परीक्षार्थियों को लखनऊ आना है या यहां के अभ्यर्थियों को संबंधित जिलों में जाना है वहां के लिए शटल सेवा चलाने का आदेश है, ताकि नियमित अंतराल पर बसें मिलती रहे।

आरएम ने बताया, बस स्टेशनों पर जिन जिलों के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी होंगे, वहां के लिए तत्काल बस भेजी जाएगी। इसीलिए हर डिपो में रिजर्व बसें रखने का आदेश भेजा जा चुका है। आलमबाग, कैसरबाग, अवध बस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां से बसों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अवध डिपो सत्यनारायण चौधरी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं, बस स्टेशनों पर एआरएम के अलावा अन्य स्टाफ को तीन दिनों तक 24 घंटे रहने के लिए ड्यूटी लगाई गई है।

उन्नाव में भीषण सड़क हादसा: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बस ने कार को मारी टक्कर, दो बच्चियों समेत 5 की मौत, 12 घायल

(जीएनएस)।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को नींद आने से बेकाबू बस डिवाइडर पार कर अर्टिगा कार से टकरा गई. हादसे में दो बच्चियों सहित कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए. डॉक्टर के अनुसार, घायलों का इलाज और गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

उन्नाव के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई जिसमें दो बच्चियां भी शामिल थी. वहीं, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक कार सवार सभी गोरखपुर से मथुरा की ओर जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 230.800 के पास आज सुबह करीब चार बजे ये एक्सीडेंट हुआ. बिहार नंबर की स्लीपर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी. तभी अचानक बस एक्सप्रेस वे पर चढ़कर डिवाइडर के दूसरी ओर आ गई. इसी दौरान गोरखपुर से मथुरा की ओर जा रही अर्टिगा कार से टकराकर बस 12 फीट नीचे खाई मे जा गिरी. बस पलटने से सवारियों मे चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में कार सवार 9 लोगों मे 5 की मौत हो गई.

मृतकों में दिव्या (13 वर्ष), अंजू (40 वर्ष), अमृता (5 वर्ष), धुनमुन (60 वर्ष) और चालक विनोद (45 वर्ष) शामिल हैं. कार सवार संतकबीर नगर के बताये जा रहे हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही थाना बांगरमऊ पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. हादसे में कार सवार चार लोग और बस में सवार चार यात्री घायल हुए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना, पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने राहत कार्यों की जानकारी ली और घायलों के बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए.

बस में सवार पूनम देवी ने बताया कि जब वह सो रही थी तभी अचानक बस तेज हिलने-डुलने लगी. उन्होंने अपने परिजनों को बताया. फिर थोड़ी देर बाद बस पलट गई. हादसा बस चालक को नींद आने की वजह से होना बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उल्ऊ बांगरमऊ अस्पताल के डॉक्टर सुनील राठौर ने बताया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर कार और बस से टक्कर हो गई. जिसमें 17 लोग यहां लाये गए थे. इसमें पांच लोग मृत थे. बाकी पांच लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और 7 लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया है.

भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में 12वीं उप-समिति बैठक के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निर्बाध नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया

(जीएनएस)।

भारत व मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतझ मलेशिया उप-समिति (एससीएमसी) की 12वीं बैठक 1 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मलेशियाई सशस्त्र बलों के रक्षा संचालन एवं प्रशिक्षण के सहायक चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आमेर महमूद बिन अब्दुल रहमान ने की।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और अब तक हुई निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। चर्चा में सेनाओं के बीच आपसी आदान-प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, कार्मिक स्तर की वार्ताएं, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग व उभरते रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया।

दोनों पक्षों ने नियमित द्विपक्षीय गतिविधियों के सफल संचालन की सराहना करते हुए सैन्य सहयोग को और व्यापक एवं सशक्त बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस दिशा में आपसी आदान-प्रदान, पेशेवर स्तर की वार्ताओं और एक-दूसरे के सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। प्रतिनिधिमंडलों ने रक्षा उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया।

दोनों पक्षों ने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम प्लस) के ढांचे के तहत एक-दूसरे की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग को पहले से मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रतिनिधिमंडलों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य से जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक में भारतझमलेशिया बेहतर रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ के रूप में रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, साझा हितों तथा सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत के साझा दृष्टिकोण के आधार पर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एससीएमसी दोनों देशों के बीच सेना-से-सेना के स्तर पर मुख्य सलाह-मशविरे का माध्यम है और यह रक्षा सचिव के स्तर पर होने वाली भारत-मलयेशिया रक्षा सहयोग बैठक का शुरूआती चरण है। बैठक में पिछली एससीएमसी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई और भरोसा जताया गया कि इसके नतीजे आने वाली भारत-मलयेशिया रक्षा सहयोग बैठक में सार्थक बातचीत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे।

बैठक के दौरान मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डीपीएसयू भवन का भी दौरा किया। इससे पहले, मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर भारत के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 01 जुलाई 2026 को दक्षिणी वायु कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर कमान संभाली

(जीएनएस)।

अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 01 जुलाई 2026 को दक्षिणी एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर कमान संभाली। इस मौके पर उन्हें दक्षिणी एयर कमांड के मुख्यालय में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

16 दिसंबर 1989 को भारतीय वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए इस एयर ऑफिसर ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और हायर एयर कमांड से पढ़ाई की है और लंदन (यूके) के 'रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज' से स्नातकोत्तर किया है। वे एक पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास अपाचे, मिग-21, जगुआर, मिग-29, २४-30 और राफेल जैसे अलग-अलग एयरक्राफ्ट पर 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव है।

लगभग चार दशकों के अपने बेहतरीन सर्विस करियर में, एयर मार्शल ने एक फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली है और एक प्रमुख फाइटर बेस के एयर ऑफिसर

कमांडिंग के तौर पर काम किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया है, जिनमें एयर डिफेंस कमांडर और एक कमांड में प्रशासनिक प्रभारी सीनियर ऑफिसर की ज़िम्मेदारी शामिल हैं। एयर हेडक्वार्टर में, उन्होंने असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन्स (ऑफेंसिव) और डायरेक्टर जनरल (वेपन सिस्टम्स) के पद संभाले हैं। अपनी मौजूदा नियुक्ति संभालने से पहले, एयर मार्शल पश्चिमी एयर कमांड में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर थे, जहाँ उन्होंने कई क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता को बेहतर बनाने में योगदान दिया। उनकी शानदार सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया है।

एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने एयर मार्शल मनीष खन्ना, जिन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित गया है, की जगह ली है। एयर मार्शल मनीष खन्ना देश की चार दशकों की शानदार सेवा के बाद 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए।